भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-14
उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

पीएम श्री योजना के तहत समझौता ज्ञापन को वापस लेने का प्रावधान

†*14. **श्री एम. के. राघवनः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पीएम श्री योजना के अंतर्गत केरल राज्य सरकार को धनराशि आबंटित की है, यदि हां, तो स्वीकृत, जारी और उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या राज्य सरकारों को पीएम श्री योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से पीछे हटने का अधिकार है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार पीछे हटने की प्रक्रिया के लिए क्या दिशानिर्देश और समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"पीएम श्री योजना के तहत समझौता ज्ञापन को वापस लेने का प्रावधान" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री एम. के. राघवन द्वारा दिनांक 01.12.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 14 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) : प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित है स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके पीएम श्री स्कूल बनाए जाते हैं। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करना है, समय के साथ एक उदाहरणपरक स्कूल के रूप में उभरना है, और पड़ोस के दूसरे स्कूलों को नेतृत्व भी प्रदान करना है।

पीएम श्री योजना के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्र के साथ एक सम्झौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें इन स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में विशिष्ट गुणवत्ता आश्वासन प्राप्त करने के लिए मदद करने की प्रतिबद्धता होनी है। इसके बाद, पीएम श्री स्कूलों का चयन चुनौती पद्धति के माध्यम से किया जाता है, जिसमें स्कूल उदाहरणपरक स्कूल बनने हेतु मदद के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

केरल राज्य ने 23 अक्टूबर 2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके बाद पीएम श्री स्कूलों के चयन हेतु पारदर्शी चुनौती पद्धति अपनाई जाएगी। तत्पश्चात्, केरल राज्य से पीएम श्री पोर्टल पर स्कूलों की सूचना अपलोड करने का अनुरोध किया गया है।

****